अमर उजाला

प्रवाह

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली | मंगलवार, 25 जून 2019

हमेशा खुद को अभिव्यक्त करो, खुद पर विश्वास रखो, अपने भीतर एक सफल व्यक्तित्व की तलाश करो और उसकी नकल करो।
- ब्रूस ली

मार्शल आर्ट से जुड़े अभिनेता

सपा से किनारा करते हुए मायावती ने विचारधारा पर आधारित कोई प्रभावी कार्यक्रम पेश करने के बजाय अपने भाई और भतीजे को बड़ी जिम्मेदारियां देकर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी भी उन क्षेत्रीय पार्टियों से अलग नहीं हैं, जहां एक परिवार का वर्चस्व है।

महागठबंधन का हश्र

लोकसभा चुनावों के नतीजों के बाद हुई बसपा की समीक्षा बैठक में ही मायावती ने सपा के साथ अपनी पार्टी के महागठबंधन के खत्म होने के स्पष्ट संकेत दे दिए थे, जिसकी घोषणा उन्होंने अब कर दी है। उनका यह कदम न तो अप्रत्याशित है और न ही इससे किसी को हैरत हुई होगी। मार्च, 2018 में गोरखपुर और फुलपूर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बसपा के समर्थन से सपा को मिली जीत के बाद इन दोनों पार्टियों ने राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव से ऐन पहले महागठबंधन बनाया था, लेकिन यह प्रयोग बुरी तरह से नाकाम साबित हुआ। बिना किसी वैकल्पिक कार्यक्रम और वैचारिक एका के यह गठबंधन दरअसल भाजपा के बरक्स अपना अस्तित्व बचाए रखने की कवायद ही अधिक था। दरअसल नतीजों के बाद यह साफ हो गया है कि सपा और बसपा में आपस में मतों का स्थानांतरण नहीं हुआ, दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में भाजपा का मत पचास फीसदी के करीब पहुंच चुका है। मायावती अब कह रही हैं कि अखिलेश ने उन्हें ध्रुवीकरण से बचने के लिए अधिक मुस्लिम उम्मीदवार न खड़ा करने की सलाह दी थी। मगर उनसे पूछा जा सकता है कि यह सवाल उन्होंने तब क्यों नहीं उठाया? मुश्किल यह भी है कि महागठबंधन से किनारा करते हुए बसपा सुप्रीमो ने मुद्दों और विचारधारा पर आधारित कोई प्रभावी कार्यक्रम पेश करने के बजाय अपने भाई आनंद और भतीजे आकाश को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रीय समन्वयक जैसी जिम्मेदारियां देकर साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी भी ऐसी तमाम क्षेत्रीय पार्टियों से अलग नहीं हैं, जो एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई हैं। खुद सपा आज जिस स्थिति में पहुंच गई है, उसके पीछे भी पार्टी में परिवार का नियंत्रण एक बड़ी वजह बन गया। वास्तव में देखा जाए तो तीन दशक पहले मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद सामाजिक न्याय के वैचारिक धरातल से उभरी पार्टियों ने सत्ता के लिए तमाम तरह के गठजोड़ तो बनाए, लेकिन वे जमीनी स्तर पर कोई ठोस बदलाव लाने में नाकाम रहीं। और फिर चुनाव सिर्फ अंक गणित का खेल नहीं है। सपा-बसपा-रालोद के महागठबंधन के प्रयोग ने यह भी दिखाया है कि दिल्ली और लखनऊ में बंद कमरों में शीर्ष नेता जो गठबंधन बनाते हैं, उसे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता स्वीकार करें यह जरूरी नहीं।

आर्थिक गैरबराबरी दूर करने का अवसर

लोगों द्वारा दिया गया जनादेश वाकई सरकार के लिए एक अवसर है। वह इसका लाभ आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में ले सकती है। आगामी बजट से हमें पता चलेगा कि क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

बी के चतुर्वेदी

नई सरकार को मिला भारी जनादेश इस बात का संकेत है कि भारत के लोगों को उससे काफी उम्मीदें हैं। बावजूद इसके कि उन्हें नोटबंदी, नई जीएसटी व्यवस्था के लागू होने और पेट्रोल तथा डीजल के दामों में बढ़ोतरी से काफी परेशानी का सामना करना पड़ा और लागत से कम वसूली के कारण ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक रूप से हताशा व्याप्त है। सरकार द्वारा हाल ही में जारी रोजगार से संबंधित सर्वेक्षण दिखाता है कि चार दशक में आज बेरोजगारी की दर सर्वाधिक है। इनमें से कई मुद्दों से सब वाकिफ हैं और इन पर चर्चा भी होती है, जबकि बढ़ती आर्थिक गैरबराबरी को लेकर तो कोई बात भी नहीं होती। इन चुनौतियों से निपटने में आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी महत्वपूर्ण हो सकती है।

उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे अनेक उत्तरी राज्यों में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। यदि उत्तर प्रदेश विकास पर ध्यान दे और उसे केंद्र की मदद मिलती है, तो उसे देश में आय के राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में तीन दशक लगेंगे। वर्ष 1982 में राष्ट्रीय आय में शीर्ष एक फीसदी आबादी की हिस्सेदारी 6.1 फीसदी थी और 2015 में यह बढ़कर 21.3 फीसदी या तीन गुना हो गई। उस समय नीचे से पचास फीसदी लोगों की हिस्सेदारी 23.6 फीसदी थी, जो तीन दशक के विकास के बाद गिरकर सिर्फ 14.7 फीसदी रह गई। पूरे देश में आर्थिक गैरबराबरी तेजी से बढ़ रही है। आगामी बजट में सरकार का एजेंडा इन मुद्दों के साथ ही अन्य संरचनागत मुद्दों का समाधान होना चाहिए और उसे आने वाले वर्षों का रोडमैप प्रस्तुत करना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने आने वाले वर्षों में देश की अर्थ व्यवस्था को पचास खरब डॉलर तक पहुंचाने की बात की है। पिछले पांच वर्षों के दौरान जीडीपी की औसत विकास दर सात से साढ़े सात फीसदी रही, जो कि पर्याप्त नहीं है। हाल ही में इस दर पर सरकार के एक पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार ने सवाल उठाए हैं। अगर लोगों की आय को उच्च मध्य आय वाले देशों के स्तर तक ले जाना है, तो हमें अगले दो दशकों के दौरान जीडीपी की विकास दर को नौ से दस फीसदी करने की योजना बनानी होगी। बचत दर में गिरावट आई है और निवेश और उच्च विकास के स्तर तक पहुंचने और उसे उस स्तर पर बनाए रखने के लिए बचत दर को बढ़ाकर 37 से 40 फीसदी करना होगा। व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के साथ ही निर्यात पर ध्यान देना होगा। विकास प्रक्रिया को फिर से परिभाषित करना होगा। इसे इस तरह का होना चाहिए, जिससे गरीबी में तेजी से गिरावट आए और उत्तर तथा दक्षिण के राज्यों में और विभिन्न आय समूहों में आय की असमानता घटे। आगामी बजट में नीतिगत घोषणा के साथ यह प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए।

समावेशी विकास के लिए अच्छी गुणवत्तायुक्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराना अहम है। जब तक लोग स्वस्थ न हों और विकास प्रक्रिया में भागीदार न बनें, हम उच्च विकास स्तर और व्यापक रूप से आय में समानता के स्तर को हासिल नहीं कर सकते।

कुछ समय पूर्व भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) में 109 देशों में 103 स्थान मिला था। हमारे देश में 19.6 करोड़ अल्पपोषित हैं और जीएचआई अंकमान 31.1 चीन से बदतर स्थिति में हैं, जहां जीएचआई अंकमान 7.6 है। नाटेपन और अल्पपोषण का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या उच्च बनी हुई है। शिक्षा की स्थिति भी ऐसी ही गंभीर बनी हुई है। स्कूल में पंजीयन तो बढ़ा है, लेकिन सीखने का खराब स्तर और कौशल के अभाव में हमारे बहुत से युवा रोजगार हासिल करने लायक नहीं रह जाते। हाल ही में प्रस्तुत किए गए शिक्षा नीति के मसौदे में कई उत्कृष्ट विचार हैं। हमें इसे आगे ले जाने की जरूरत है। आयुष्मान भारत एक शानदार पहल है, लेकिन चिकित्सा ढांचे का विस्तार अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अस्पताल के बुनियादी ढांचे और मेडिकल कॉलेजों का विस्तार और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बेहतर स्वास्थ्य सूचकांक, दीर्घायु, कम शिशु मृत्यु दर और तेजी से कम होने वाली मातृ मृत्यु दर प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगी। सारी अर्थव्यवस्थाओं के विकास में आधारभूत संरचना महत्वपूर्ण होती है और हमें इस क्षेत्र में अगले दशक में बीस से तीस खरब डॉलर निवेश करने की जरूरत होगी। संचार को बेहतर करने के लिए दूरसंचार, रेलवे और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने, आधुनिकीकरण करने और इसमें भारी निवेश करने की जरूरत है। ऊर्जा की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए हमें कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने की हमारी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना होगा।

अगले तीन दशकों में शहरीकरण का स्तर तेजी से बढ़ेगा और अंदाजा है कि यह आज के स्तर से दोगुना हो जाएगा। ऐसे में हमें नई शहरों के समूहों के बारे में विचार करना चाहिए, जो हमारी अगले पांच दशकों की जरूरतों को पूरा कर सकें। इन नए शहरों में सड़क, सीवर, पीने के पानी की लाइन और बिजली वितरण प्रणाली को ध्यान में रखना होगा। इसमें तुरंत निवेश की जरूरत होगी।

भारत तब तक आधुनिक लोकतंत्र नहीं बन सकता, जब तक कि शासन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार न हो। इससे भ्रष्टाचार को कम करने में और विकास को गति देने में मदद मिलेगी। इससे नागरिकों का जीवन बेहतर होगा। यह हमें शीर्ष वैश्विक लोकतंत्र की हमारी नियति की ओर ले जाएगा। इसके लिए हमें केंद्र और राज्यों में रिफॉर्म ग्रुप बनाने की जरूरत है, जो कि जन हितैषी कानून और प्रक्रिया बनाएं। दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां ध्यान देने की जरूरत है जहां लंबे समय से सुधारों की आवाजें आ रही हैं और ये हैं पुलिस और न्यायपालिका। लोगों द्वारा दिया गया भारी जनादेश वाकई सरकार के लिए एक अवसर है। वह इसका लाभ आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और संपत्ति की असमानता को दूर करने और शासन से जुड़े कुछ बुनियादी मुद्दों को सुलझाने में कर सकती है। आगामी बजट से हमें पता चलेगा कि क्या हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

-पूर्व कैबिनेट सचिव, और पूर्व सदस्य योजना आयोग।

अंतर्ध्वनि

>> फैज अहमद फैज

बचपन में मैं शायर नहीं, बल्कि क्रिकेटर बनना चाहता था

हमारे घर में औरतों का एक हुजूम था। हम जो तीन भाई थे, उनमें हमारे छोटे भाई और बड़े भाई घर की औरतों से बागी होकर खेलकूद में जुटे रहते थे। हम अकेले उन खवातीन के हाथ आ गए। उसका फायदा यह हुआ कि उन महिलाओं ने हमको शरीफाना जिंदगी बसर करने पर मजबूर किया। नुकसान यह हुआ कि बचपन के खिलंदड़ेपन से हम कटे रहे। हमारे घर से मिली हुई एक दुकान थी, जहां किताबें किराये पर मिलती थीं। वहीं से लेकर दाग का कलाम पढ़ा। मीर का कलाम पढ़ा। गालिब तो

उस वक्त हमको ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन उनका दिल पर कुछ अलग किस्म का असर होता था। यों, शेर से लगाव पैदा हुआ और साहित्य में दिलचस्पी होने लगी। जब दसवीं जमात में पहुंचे, तो हमने भी तुकबंदी शुरू कर दी। शुरू-शुरू में हमें कोई खयाल ही न गुजरा कि हम शायर बनेंगे। शुरू में खयाल हुआ कि हम कोई बड़े क्रिकेटर बन जाएं, क्योंकि लड़कपन से क्रिकेट का शौक था। फिर जी चाहा कि उस्ताद बनना चाहिए। हम क्रिकेटर बने, न आलोचक। अलबत्ता उस्ताद (प्राध्यापक) होकर अमृतसर चले गए। हमारी जिंदगी का शायद सबसे खुशगवार जमाना अमृतसर का ही था। जब हमें पहली दफा पढ़ाने का मौका मिला, तो बहुत लुत्फ आया। उस जमाने में कुछ संजीदगी से शेर लिखना शुरू किया। अमृतसर में ही पहली बार सियासत में थोड़ी-बहुत सूझ-बूझ पैदा हुई। मजदूरों में काम शुरू किया। प्लेस में काम किया। इन सबसे मानसिक-बौद्धिक संतोष का एक बिल्कुल नया मैदान हाथ आया। हम देहली जाने लगे, तो वहां नए-नए लोगों से मुलाकात हुई। मजाज, सरदार जाफरी, जांनिसार अख्तर, जज्बी और मख्दूम मरहूम से रेडियो के जरिये संपर्क हुआ, जिससे दोस्ती के अलावा समझ और सूझ-बूझ में तरह-तरह के इजाफे हुए।

-भारतीय उपमहाद्वीप के चर्चित शायर।

मंजिलें और भी हैं

>> धनंजय चौहान

लड़कर हासिल किया ट्रांसजेंडर का अधिकार

बचपन से ही अलग सेक्सुअल पहचान की वजह से मुझे लोगों की प्रताड़नाओं का शिकार होना पड़ा। मैं शरीर से भले लड़का थी, लेकिन मन से लड़की। स्कूल, कॉलेज, घर, तकरीबन हर जगह मैं घुटी-घुटी-सी रहती थी। पढ़ाई छूटने के बाद मैंने नौकरी भी की, लेकिन वहां भी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। सिर्फ दो जेंडर्स (लिंग) होने की अवधारणा समाज में इस तरह जड़ जमा चुकी है कि लोग यह समझ ही नहीं पाते कि तीसरा जेंडर होना भी सामान्य बात है और ऐसे लोगों को वे समाज में बिल्कुल जगह नहीं देना चाहते। वे हमें कुछ देते हैं तो बस गंदी गालियां और भयंकर तनाव।

तब मैं चंडीगढ़ की पंजाब विश्वविद्यालय में परास्नातक की पढ़ाई कर रही थी। शुरू के कुछ दिन तो ठीक रहे लेकिन जल्द ही मेरी कक्षा के छात्र मेरी सेक्सुअलिटी को लेकर मेरा मजाक उड़ाने लगे। तनाव जब बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मजबूरन मैंने पढ़ाई छोड़ दी। लेकिन पढ़ने की ललक बनी रही। मैंने सोचा कि दूरस्थ शिक्षा से पढ़ाई जारी रखी जाए। मैंने रूसी और फ्रेंच भाषाओं के साथ कम्प्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया। इसके बाद इग्नू से सामाजिक कार्य विषय में परास्नातक किया। लगातार प्रताड़ना के बाद पढ़ाई व नौकरी छोड़ने के कारण मेरा मन ऊब गया। मैं अकेलापन महसूस करने लगी, तब किताबें मेरा सहारा बनीं। किताबों से ही पता चला कि अपने अधिकारों के लिए मुझे ही लड़ाई लड़नी होगी और इसे कमरे में बंद रहकर नहीं लड़ा जा सकता। इसके लिए बाहर निकलना होगा और अपने जैसे लोगों से जुड़कर समाज में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करना होगा। उस समय मेरी मुलाकात कई ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट से हुई। उनसे मिलने के बाद मैंने चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों के लिए काम शुरू कर दिया। उस समय देश-विदेश में ट्रांसजेंडर 'प्राइड वॉक' नाम से सड़कों पर उतरते थे। मैंने भी चंडीगढ़ में 'प्राइड वॉक' का आयोजन करवाया। इस आयोजन ने मेरे संघर्ष को नई ऊंचाई दी। वर्ष 2014 में 'नाल्सा जजमेंट' को लागू करवाने के लिए हुए आंदोलन में मैंने सक्रियता से भाग लिया। इस आंदोलन में हमारी जीत हुई और अब जेंडर वाले कॉलम में दो की जगह तीन कॉलम हो गए। तीसरा कॉलम ट्रांसजेंडर्स का था। इस जीत के बाद वह दिन आया जिसके लिए मैंने यह संघर्ष किया। मैंने मानवाधिकार और कर्तव्य विषय से परास्नातक करने के लिए पंजाब विश्वविद्यालय में दोबारा एडमिशन लिया। पर इस बार पहचान छिपाकर नहीं, बल्कि अपनी अलग पहचान के दम पर। इस तरह मैं पंजाब विवि से परास्नातक करने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। इसके बाद ट्रांसजेंडर्स को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने का लक्ष्य बनाते हुए मैंने विश्वविद्यालय में ट्रांसजेंडर के लिए सुविधाओं और फीस माफी का अनुरोध करते हुए कई पत्र लिखे, जिसे प्रशासन ने मान लिया। इसके बाद कई ट्रांसजेंडर्स ने पंजाब विवि में दाखिला लिया है। जब मुझे जरूरत थी, तब मेरे परिवार ने मेरा सहयोग नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे हिजड़ा बाड़े में रहना पड़ा। अब वह मेरे साथ आना चाहते है क्योंकि मैं प्रसिद्ध हो गई हूं। लोग मुझे जानने लगे हैं। मैं जानती हूं कि रास्ता कठिन है, पर मुझे लगता है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है, जो ट्रांसजेंडर्स को मुख्यधारा से जोड़ने का काम कर सकता है। यही वजह है कि मैंने अपने हाथों में विद्या का दंड थाम लिया है और निकल पड़ी हूं अपने ही समान दूसरे लोगों को शिक्षा दिलवाने के लिए।

वर्ष 2014 में 'नाल्सा जजमेंट' को लागू करवाने के लिए हुए आंदोलन में सक्रियता से भाग लिया।

-विभिन्न साक्षात्कारों पर आधारित।

नौसेना को और पनडुब्बियां चाहिए

रक्षा कर्णधारों ने 1999 में तय किया था कि 2030 तक नौसेना के पास 24 पनडुब्बियां होनी चाहिए। पर अगले दशक के अंत तक उसके पास करीब एक दर्जन पनडुब्बियां ही रहेंगी, जो हिंद और प्रशांत महासागरों की रक्षा के लिए नाकाफी होंगी।

रंजीत कुमार

रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में नौसेना के लिए छह नई पनडुब्बियां हासिल करने के करीब 45,000 करोड़ रुपये के सौदे के लिए आरंभिक टेंडर जारी कर दिया। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में एक महीने के भीतर सैन्य ताकत मजबूत करने का यह पहला बडा कदम उठाया गया है। इन पनडुब्बियों की मंजूरी 2007 में ही मिल गई थी, पर पिछले बारह साल से विभिन्न सरकारें इसके सौदे और निर्माण की प्रक्रिया के बारे में ही उलझी रहीं। हालांकि यह सौदा संपन्न करने से लेकर इन्हें नौसेना को सौंपने में एक दशक से भी अधिक का वक्त लग सकता है। यह प्रसंग बताता है कि भारतीय सैन्य तैयारी किस तरह राजनीतिक अनिश्चितता का शिकार बनती है।

हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए समुचित संख्या में नए पोत हासिल करने की भारी जरूरत महसूस की जा रही थी। कारगिल युद्ध के बाद देश के सामने पैदा नई सामरिक चुनौती के अनुरूप दो नई पनडुब्बी निर्माण सुविधा बनाने का नीतिगत फैसला लिया गया था। इसके तहत प्रोजेक्ट-75 के अंतर्गत 2006 में फ्रांस के सहयोग से मुंबई की मझगांव गोदी में छह स्कारपीन पनडुब्बियां बनाने का करीब 23,000 करोड़ रुपये का सौदा किया गया था। उसके एक साल बाद छह नई पनडुब्बियां देश में ही भारतीय कंपनियों को साथ लेकर बनाने को मंजूरी दी गई थी।

प्रोजेक्ट-75 के तहत स्कारपीन वर्ग की दो पनडुब्बियां नौसेना को पिछले दो साल में सौंपी जा चुकी हैं, जबकि बाकी निर्माण की विभिन्न अवस्था में हैं। हमारे रक्षा कर्णधारों ने 1999 में तय किया था कि 2030 तक नौसेना के पास 24 पनडुब्बियां होनी चाहिए। फिलहाल नौसेना के पास रूसी किलो वर्ग की जो नौ पनडुब्बियां हैं, वे दो दशक से अधिक पुरानी हो चुकी हैं। जर्मन टाइप-209 वर्ग की चार पनडुब्बियां भी दो दशक से अधिक पूरानी हो चुकी हैं। अगले दशक के अंत तक जब इन दोनों वर्गों की पनडुब्बियों को रिटायर करना होगा, तब तक नौसेना के पास केवल स्कारपीन वर्ग की छह पनडुब्बियां ही बचेंगी औरे रूस से लीज पर ली गई एक परमाणु पनडुब्बी को रूस को लौटाना होगा। नौसेना की एकमात्र अरिहंत परमाणु पनडुब्बी के अलावा दो और परमाणु पनडुब्बी 2030 तक नौसेना में शामिल हो सकेंगी। यानी अगले दशक के अंत तक करीब एक दर्जन पनडुब्बियां ही बचेंगी।

सवाल यह उठता है कि 2030 तक हिंद महासागर से प्रशांत महासागर तक के इलाके में निरंतर चौकसी की बढ़ी जिम्मेदारी सीमित पनडुब्बियों से कैसे पूरी होगी। नौसेना को ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीकी तट और फारस की खाड़ी से मलक्का तक अपने विशाल समुद्री इलाके में पनडुब्बियों की क्षमता निरंतर बढ़ाते रहने की जरूरत है, क्योंकि अगले कुछ साल में हिंद महासागर के इलाके के बड़ी ताकतों का अखाड़ा बन जाने की पूरी आशंका है।

चूंकि फिलहाल नई पनडुब्बियां हासिल करने की हमारी कोई और योजना नहीं है, ऐसे में, हमारी नौसेना हिंद महासागर में टोह लेने की अपनी वांछित क्षमता से कहीं पीछे रहेगी। जबकि हमें पनडुब्बी क्षमता का विकास अपने मुख्य प्रतिद्वद्वी देशों चीन और पाकिस्तान की पनडुब्बी क्षमता के मद्देनजर करना होगा। चीन के पास परमाणु और डीजल पनडुब्बियों सहित 68 और पाकिस्तान के पास दस डीजल पनडुब्बियां हैं, जो हिंद महासागर के इलाके में भारत के लिए चुनौती बन सकती हैं। इनसे मुकाबला के लिए हमारी नौसेना की पनडुब्बी क्षमता में तत्काल समुचित बढ़ोतरी की जरूरत है।

हरियाली और रास्ता

रिकी, वेटर और वडा पाव

यह कहानी उस लड़के की है, जिसने एक बूढ़े वेटर को इनाम देकर उसके महत्व का एहसास कराया।

रिकी बीस मिनट से मेनू कार्ड पलटे जा रहा था। काउंटर पर लोगों की लाइन लंबी हो रही थी। वेटर रिकी को गुस्से से देख रहा था। पहले भी दो बार वह उससे ऑर्डर लेने जा चुका था। पर रिकी ने चीजों के दाम पूछकर उसे वापस भेज दिया था। उसकी वजह से बाकी ग्राहक लौट सकते थे। वेटर फिर रिकी का ऑर्डर लेने आया। रिकी ने पूछा, प्लेन पिज्जा के कितने रुपये बताए थे? वेटर बोला, 120 रुपये। रिकी ने पूछा, और यदि उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लें, तो? वेटर बोला, कोल्ड ड्रिंक 40 रुपये की है। रिकी ने पूछा, और यदि पनीर पिज्जा लें, तो? वेटर बोला, वह 170 का होगा। रिकी बोला, अगर एक बर्गर लें, तो? वेटर बोला, बर्गर 60 रुपये का है। रिकी बोला, तो 60 रुपये में कोल्ड ड्रिंक और बर्गर, दोनों आ जाएंगे? वेटर बोला, नहीं, सिर्फ बर्गर। रिकी काफी देर तक सोचता रहा। फिर बोला, आप एक वडा पाव ले आइए। वह कितने का है? वेटर बोला, 30 रुपये का। थोड़ी देर में रिकी का वडा पाव आया। बाहर इंतजार करते लोगों की लाइन लंबी होती जा रही थी।

वेटर रिकी को कोस रहा था। जल्दी ही रिकी बिल जमा कर निकल गया। बाद में जब वेटर टेबल साफ करने वहां पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां एक चिट्ठी और सौ का नोट पड़ा है। चिट्ठी में लिखा था, आज मेरी परीक्षा का रिजल्ट आया था। मैं फर्स्ट आया हूं। पिता जी ने दोस्तों के साथ जश्न मनाने के लिए मुझे 200 रुपये दिए थे। 50 रुपये की मैंने दोस्तों को मिठाई खिला दी। 20 रुपये गुल्लक के लिए जमा कर लिए। 30 का वडा पाव आपके हाथ से खाया। और बाकी बचे 100 रुपये मैं आपके लिए छोड़ जा रहा हूं। मेरी मेहनत का तो इनाम मिल गया। पर आप जो इतने वर्षों से कर रहे हैं, उसे शायद कोई नहीं देख पाता।

हर किसी को एक ही सांचे में रखकर नहीं देखना चाहिए।

खुली खिड़की

मशरूम का निर्यात

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक बाजार में मशरूम की मांग तेजी से बढ़ी है। मांग के अनुरूप अभी भी इसके उत्पादन की क्षमता में कमी है। 2018 में आई रिपोर्ट के मुताबिक मशरूम का बड़ा निर्यातक पोलैंड है।

आंकड़े लाख डॉलर में हैं।

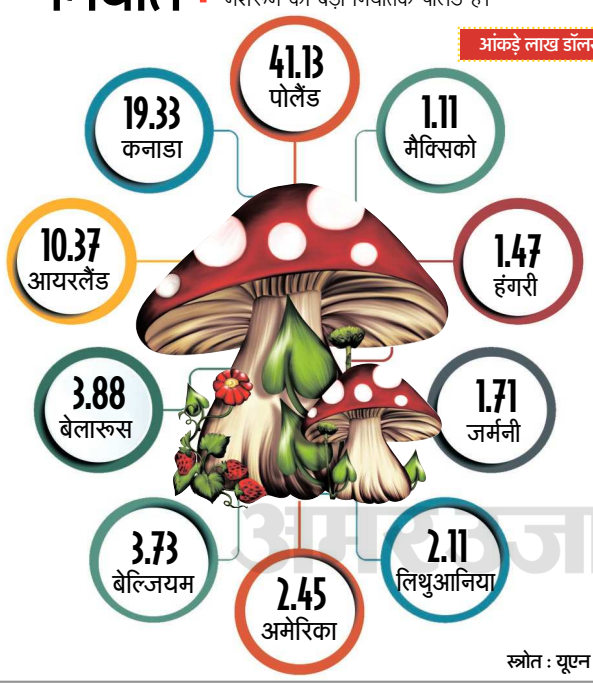

स्रोत : यूएन कमट्रेड

सत्संग

सच को दबाना ठीक नहीं

यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात अपने शिष्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में व्यस्त थे। तभी एक ज्योतिषी घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। उसका दावा था कि वह चेहरा देखकर व्यक्ति के बारे में बता देता है। सुकरात थोड़े बदसूरत थे, पर लोग उनके अच्छे विचारों के कारण उन्हें बहुत पसंद करते थे। ज्योतिषी सुकरात के चेहरे को देखकर कहने लगा, आपके नथुनों की बनावट बता रही है कि आपमें क्रोध की भावना प्रबल है। यह सुन सुकरात के शिष्य नाराज हो गए, पर सुकरात ने अपने शिष्यों को रोक कर ज्योतिषी को अपनी बात कहने का पूरा मौका दिया। ज्योतिषी ने आगे कहा, आपके माथे और सिर की आकृति को देखकर लगता है कि आप बहुत लालची हैं। आपकी ठोढ़ी की रचना कहती है कि आप सनकी हैं। जबकि होठों और दांतों की बनावट के मुताबिक, आप सदैव देशद्रोह के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। यह सुनकर सुकरात ने ज्योतिषी को धन्यवाद दिया और वापस भेज दिया। सुकरात के शिष्य भौचक्के रह गए। सुकरात ने शिष्यों की जिज्ञासा शांत करते हुए कहा कि सच को दबाना ठीक नहीं। ज्योतिषी ने जो कुछ बताया, वे सभी दुर्गुण मुझमें हैं। पर ज्योतिषी से यह भूल हुई है कि उसने मेरी विवेक शक्ति पर जरा भी ध्यान नही दिया। मैं अपनी विवेक शक्ति से इन सभी दुर्गुणों पर अंकुश लगाए रखता हूं। ज्योतिषी शायद यह बताना भूल गए।

-संकलित